www.tamsasanket.com
वर्ष: 05 || अंक 316 || लखनऊ
गुरुवार
19 फ़रवरी 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 06:40
सूर्यास्त: 06:01
अधिकतम: 28°00
न्यूनतम: 15°00

पेज 03

विशेष समाचार | जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा ... >> पेज 02 | लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगे 'भागवत ... >> पेज 04 | सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा ...

गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर

पहले चीनी रोबोट, फिर ड्रोन को अपना बताया, कांग्रेस बोली- सरकार ने देश की इमेज खराब की

कार्रवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो से बाहर निकाल दिया गया है। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी, फिर ताला लगाकर बेरीकेडिंग कर दी गई। यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज कंपनी के रोबोटिक डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था। चीनी रोबो डॉग के साथ ही यूनिवर्सिटी ने कोरियन कंपनी के एक ड्रोन को भी अपना बताया था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने देश की इमेज खराब की है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। चीन की कंपनी यूनिट्री ने इस रोबोटिकक डॉग को बनाया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे अपना इंवेंशन बताया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि यह असल में चीनी कंपनी 'यूनिट्री' का 'Go2' मॉडल है, जो बाजार में 2-3 लाख रुपए में उपलब्ध है। वहीं एक अन्य वीडियो में यूनिवर्सिटी जिस ड्रोन को कैंपस में 'शुरुआत से' तैयार करने का दावा कर रही हैं, उसे यूजर्स ने 40 हजार वाला रेडीमेड 'स्ट्राइककर V3 ARF' मॉडल बताया है। इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होती। सीखने की भी नहीं होनी चाहिए। हम दुनियाभर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाना जारी रखेंगे ताकि हमारे छात्र उनका अध्ययन कर सकें, उन्हें चुनौती दे सकें और उनमें सुधार कर सकें और अंत में वर्ल्ड-क्लास समाधान तैयार कर सकें। यूनिट्री Go2 चीन की यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया एक एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है।

>> (शेष पेज 04 पर)

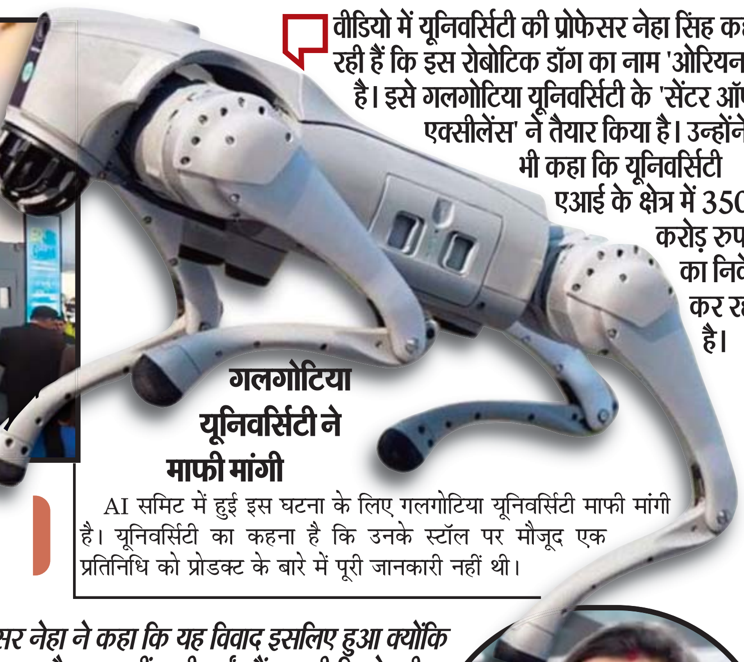

वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही हैं कि इस रोबोटिक डॉग का नाम 'ओरियन' है। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी एआई के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।

चीन की कंपनी यूनिट्री ने इस रोबोटिकक डॉग को बनाया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे अपना इंवेंशन बताया था।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी

AI समिट में हुई इस घटना के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी माफी मांगी है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनके स्टॉल पर मौजूद एक प्रतिनिधि को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी।

यूनिवर्सिटी ने माना था, हमने नहीं बनाया ये डॉग

वीडियो वायरल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा- हमने लगातार कैंपस में बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि जब छात्र नई चीजें देखते हैं, तभी उनकी सोच विकसित होती है। और यही सोच नए रचनाकारों को जन्म देती है। हाल ही में यूनिट्री से लिया गया रोबोटिक डॉग इसी सफर का एक हिस्सा है। यह सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई कोई मशीन नहीं है, यह एक चलता-फिरता क्लासरूम है। हमारे छात्र इस पर प्रयोग कर रहे हैं, इसकी क्षमताओं को परख रहे हैं और इस प्रक्रिया में अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि गलगोटिया ने यह रोबोटिक डॉग नहीं बनाया है और न ही हमने कभी ऐसा दावा किया है। लेकिन हम ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही भारत में ऐसी ही टेक्नोलॉजी को डिजाइन करेंगे, उनकी इंजीनियरिंग करेंगे और उन्हें यहीं बनाएंगे।

प्रोफेसर नेहा ने कहा कि यह विवाद इसलिए हुआ क्योंकि बातें साफ तौर पर नहीं रखी गईं। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं। यह सब बहुत जोश और उत्साह में बहुत जल्दी-जल्दी हुआ। यूनिवर्सिटी के स्पष्टीकरण के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने इस पोस्ट पर एक 'कम्युनिटी नोट' जोड़ दिया। इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी का यह दावा कि उन्होंने इसे अपना नहीं बताया, भ्रामक है। एक्स का कम्युनिटी नोट एक ऐसा फीचर है, जिसमें आम यूजर्स ही किसी भ्रामक पोस्ट पर सही जानकारी और संदर्भ जोड़कर उसे फैक्ट-चेक करते हैं।

2011 में शुरू हुई थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी

ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी 2011 में शुरू हुई थी। ये यूनिवर्सिटी 20 अलग-अलग स्कूलों के जरिए डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के 200 से ज्यादा कोर्स कराती हैं। सुनील गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चांसलर और ध्रुव गलगोटिया CEO हैं।

कांग्रेस बोली- मोदी सरकार ने दुनिया में देश का मजाक बनवाया

कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि मोदी सरकार ने AI के मामले में दुनिया भर में भारत का मजाक बनवाया है। AI समिट में चीन के रोबोट्स को हमारा बताकर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी झूठ में शामिल हैं और भारतीय समिट में चीन के रोबोट्स को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत के टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय, यह AI समिट एक 'डिसऑर्गनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल' बनकर रह गया है।

रोबोटिक डॉग और ह्युमनॉइड रोबोट बनाती है यूनिट्री

यूनिट्री चीन की एक मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो हाई-परफॉर्मेंस वाले रोबोटिक डॉग और ह्युमनॉइड रोबोट बनाने के लिए दुनियाभर में जानी जाती है। यह कंपनी मुख्य रूप से किफायती और एडवांस सेंसर वाली रोबोटिक्स तकनीक विकसित करती है, जिसका इस्तेमाल रिसर्च, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल कामों के लिए किया जाता है।

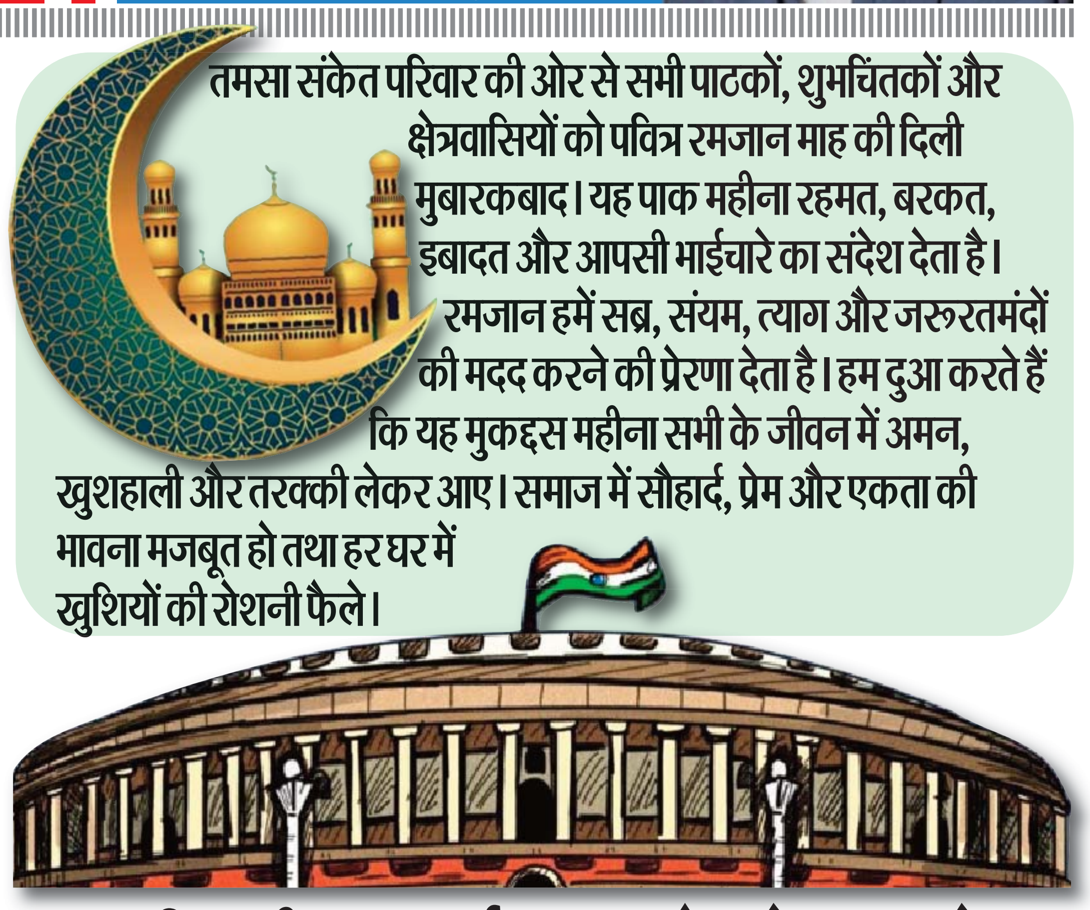

पवार, सिंघवी का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा

राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव

ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास हैं, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल-बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। शरद पवार, रामदास अठावले, कणिमोझी, तिरुचि शिवा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।

>> (शेष पेज 04

शरद पवार, अभिषेक सिंघवी और रामदास अठावले सहित कई बड़े नेता राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं।

12 एनडीए के पास हैं
25 पर विपक्ष का कब्जा है

आयोग ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।

फास्ट न्यूज

रोहित पवार ने एविएशन मिनिस्टर को हटाने की मांग की

मुंबई। शरद गुट की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने बुधवार को सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर के. राममोहन नायडू को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नायडू VSR कंपनी को बचा रहे हैं। रोहित ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- जिस VSR कंपनी का लियरजेट विमान 28 जनवरी को बारामती में क्रैश हुआ, उसे बचाने की कोशिश हो रही है।

पंजाबी एनआरआई दूल्हे की शादी में नोटों की बारिश

अमृतसर। तरनतारन जिले के पट्टी क्षेत्र में एक NRI की शादी पंजाब में चर्चा का विषय बन गई। शादी समारोह के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दिख रहा है कि दूल्हा अपनी दुल्हन पर नोटों की बारिश कर रहा है। इस दौरान रिश्तेदार खड़े होकर इस सीन को देख रहे हैं। जबकि, कुछ लोग इस सीन को एन्जॉय कर डांस कर रहे हैं और वे भी नोट उड़ा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दूल्हा बैग में भरकर नोट लाया था, जिसने गड्डियां खोल-खोलकर नोट लुटाए। इस दौरान उसने 8 से 9 करोड़ रुपए उड़ा दिए। हालांकि, शादी में डीजे बजाने पहुंचे युवक ने इन दावों को गलत बताया। उसने कहा- नोटों में 10-10 के नोट ज्यादा थे, इसलिए रुपयों की संख्या ज्यादा लग रही है।

किसानों और पुलिस के बीच पथराव

बठिंडा। बठिंडा के जिओंद गांव के पास पुलिस और किसानों के बीच भारी टकराव हो गया। किसानों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस टकराव में पुलिस और किसानों की ओर से कई लोग घायल हुए हैं।

आप सरपंच की गोली मारकर हत्या

तरनतारन फार्म हाउस में चचेरे भाई की शादी में बराती बनकर घुसे हमलावर

- घटना के बाद सिद्धू फार्म हाउस पहुंची पुलिस।
- अस्पताल में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर सरपंच के परिजनों से मिले।
- फायरिंग के बाद मौके पर जांच करती हुई पुलिस।

तमसा संकेत, एजेंसी

मानव, तरनतारन/अमृतसर। तरनतारन में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच हरबिंदर सिंह (45) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार (18 फरवरी) को सिद्धू फार्म में उनके चचेरे भाई की शादी थी। इसी में दोपहर करीब ढाई बजे हमलावर बराती बनकर अंदर घुसे। इस बीच जब सरपंच स्टेज पर दोस्तों के साथ डांस करने के बाद सोफे पर बैठे तो भीड़ में से एक युवक निकला और उनके पेट और सिर में 4 गोलियां मार दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान जब चचेरे भाई जर्मनजीत सिंह ने हमलावरों का पीछा किया तो उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी।

ईडी केंद्र का हथियार : ममता सरकार

एजेंसी ने कहा- हमें बंगाल में धमकाया, एससी बोला- हम तय करेंगे कौन हथियार और किसे धमकाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब मांगा था। 2 फरवरी को राज्य सरकार ने नोटिस के जवाब में कहा- एजेंसी की याचिका सुनवाई लायक नहीं है। इस तरह का मामला पहले से कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए दो सवैधानिक अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं हो सकती।

रेड के दौरान फाइलें लेकर चली गईं थी सीएम ममता

सर्च ऑपरेशन के दौरान, CM ममता बनर्जी अन्य TMC नेताओं के साथ I-PAC ऑफिस पहुंचीं। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। ममता ऑफिस से कई फाइलें लेकर बाहर निकलीं और मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर हद से ज्यादा दखलंदाजी का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि I-PAC पार्टी के चुनाव रणनीतिकार के रूप में काम करता है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ED ने गोपनीय चुनाव रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए रेड डाली।

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल में I-PAC से जुड़े रेड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) का उन राज्यों में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जहां विपक्ष की सरकार है।

>> (शेष पेज 04 पर)

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की 3 बड़ी दलीलें...

- रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचीं और इलेक्ट्रोनिक डिवाइस और दस्तावेज अपने साथ ले गईं। ममता के साथ बंगाल DGP भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ED अफसरों के मोबाइल छीन लिए। CM मीडिया के सामने भी गईं। इस तरह ED का मनोबल गिरता है। उनके काम में बाधा आती है।
- हम 14 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट नहीं है। हमें काफी परेशानी हुई। सुनवाई के दौरान बार-बार माइक बंद हो रहा था। कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए को बस और गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी।
- ED आर्टिकल 21 के तहत अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। ED अधिकारियों को धमकियां दी गई थीं। हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं CBI मामले की जांच करें। मामला CBI के पास गया तो मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है।

0000 : 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देंगे, पीएम बोले- गूगल के साथ साझेदारी पर चर्चा हुई

सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज यानी 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम ने कहा कि हमने भारत में AI के क्षेत्र में हो रहे काम और गूगल कैसे हमारे युवाओं के साथ काम कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की। समिट के इतर हुई इन बैठकों का उद्देश्य AI में भारत की लीडरशिप को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। पिचाई 'ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026' में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। 20 फरवरी को वे इस समिट में की-नोट एड्रेस (मुख्य भाषण) देंगे। PM मोदी से मुलाकात के बाद सुंदर पिचाई दिल्ली में मीडिया रिसेप्शन में पहुंचे। यहां

उन्होंने कहा की गूगल 'कर्मयोगी भारत' मिशन के तहत 2 करोड़ कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग देगा। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ भी अलग-अलग बैठकें कीं। PM मोदी से मुलाकात के बाद सुंदर पिचाई दिल्ली में मीडिया रिसेप्शन में शामिल हुए।

>> (शेष पेज 04 पर)

मीडिया रिसेप्शन में सुंदर पिचई की 5 सबसे बड़ी बातें

- **70,000 करोड़ का निवेश:** भारत और अमेरिका के बीच समुद्र के नीचे सीधी 'इंटरनेट केबल' बिछाई जाएगी, जिससे AI और डेटा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी।
- **2 करोड़ कर्मचारियों को ट्रेनिंग:** गूगल 'कर्मयोगी भारत' मिशन के तहत 800 जिलों के कर्मचारियों को 18 भाषाओं में AI इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देगा।
- **'सर्च लाइट' टूल:** भारतीय यूजर्स के लिए नया फीचर आ रहा है, जिससे वे अपनी लोकल भाषा में सिर्फ बोलकर या कैमरे के जरिए फोटो खींचकर जानकारी सर्च कर सकेंगे।
- **1.1 करोड़ छात्रों को कोडिंग:** गूगल 10,000 स्कूलों के बच्चों को कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाएगा; साथ ही युवाओं के लिए हिंदी-अंग्रेजी में 'AI सर्टिफिकेट प्रोग्राम' शुरू होगा।
- **विज्ञान के लिए 250 करोड़:** बीमारियों के इलाज और सटीक मौसम की भविष्यवाणी के लिए गूगल वैज्ञानिकों को 250 करोड़ ($30M) का ग्लोबल रिसर्च फंड देगा।

दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी और गूगल CEO सुंदर पिचाई ने मीटिंग की।

मैं गांधियन-राजीवियन हूं, राहुलियन नहीं : मणिशंकर अय्यर

वे राजनीतिक जीवन में मुझसे बहुत दूर, इंदिरा ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को तानाशाही में बदला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली2। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बुधवार को कहा कि वे खुद को गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी मानते हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनसे करीब 30 साल छोटे हैं और उन्हें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। इसलिए खुद को राहुलवादी कैसे कह सकता हूं? बातचीत में अय्यर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद को इंदिरावादी नहीं कहा, क्योंकि वे इंदिरा गांधी के आपातकाल घोषित किए जाने से असहमत थे। उनके मुताबिक लोकतंत्र को 18 महीनों के लिए तानाशाही में बदलना मुझे मंजूर नहीं था। मंगलवार को अय्यर ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी विरोध को सहन नहीं कर सकती, तो यह उसके लिए खतरे की बात है। उन्होंने कई कड़े बयान भी दिए। अय्यर ने शशि थरूर को सिद्धांतों के बिना अपना करियर बनाने वाला बताया। उन्होंने केसी वेणुगोपाल को गुंडा कहा और पार्टी के पुराने नेता रमेश चेन्निथला की भी आलोचना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब वे छह साल के थे और उनके भाई चार साल के, तब महात्मा गांधी ने उन्हें गोद में उठाकर कहा था कि ये मेरी आंखों के सूरज और चांद हैं। उसी समय से वे खुद को गांधीवादी मानने लगे। उन्होंने आगे कहा कि जब जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तब वे छह साल के थे और 23 साल के होने तक नेहरू प्रधानमंत्री रहे। इसलिए उनके पूरे बचपन और युवावस्था पर नेहरूवादी सोच का गहरा असर पड़ा, और वे खुद को नेहरूवादी भी मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद को राजीववादी कहते हैं, क्योंकि राजीव गांधी ही थे जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में काम करने का मौका दिया। राजीव गांधी उनसे दो साल छोटे थे, लेकिन उनके कामों से वे बहुत प्रभावित हुए। इसी वजह से वे खुद को राजीववादी बताते हैं। अय्यर का यह बयान ऐसे समय में आया है।

>> (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

सरकारों के काम करता सुप्रीम कोर्ट

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी और विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के मामलों को डकैती और लूट करार देते हुए केंद्र सरकार को कई निर्देश दिए। उसने गृह मंत्रालय को हाल में तैयार मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू करने, सीबीआई को मामलों की पहचान करने और रिजर्व बैंक को संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन रोकने के निर्देश दिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए एक मसौदा तैयार करने को भी कहा। उसने जब डिजिटल अरेस्ट के एक मामले का स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामलों की सुनवाई शुरू की थी, तब गृह मंत्रालय ने एक एसओपी का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और जहां संभव हो, ठगी से निकाली गई राशि की समयबद्ध वापसी सुनिश्चित करना था। यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े सभी पहलुओं की व्यापक जांच के लिए एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समिति का गठन किया था। इसी समिति ने एसओपी का प्रस्ताव तैयार किया। प्रश्न यह है कि गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए जो जतन करने शुरू किए, वे उसकी ओर से समय रहते स्वतः क्यों नहीं किए हुए और वह भी तब जब डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हों? चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए साइबर ठगी रोकने का काम मुख्यतः राज्य सरकारों का ही है, लेकिन केंद्र सरकार बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भूमिका पर तो ध्यान दे ही सकती थी। इस पर गौर करें कि सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में बैंकों की भूमिका को संदिग्ध पाया और इससे तो सभी परिचित हैं कि डिजिटल अरेस्ट समेत साइबर ठगी के अधिकतर मामलों में वाट्सएप की भूमिका रहती है। साइबर धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि डिजिटल फ्रॉड के जरिये अब तक 54 हजार करोड़ से भी ज्यादा की रकम हड़पी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। क्या यह विचित्र नहीं कि लोगों की हजारों करोड़ रुपये की गाढ़ी कमाई लूटी जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर इस पर वैसी कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा, जैसी अब वह शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर कर रही है? साइबर ठगी पर राज्य सरकारें भी कम लापरवाह नहीं। एक आंकड़ा यह कहता है कि 2021 से 2023 के बीच डिजिटल फ्रॉड की 48 लाख शिकायतों के मुकाबले केवल दो लाख एफआईआर दर्ज हुईं। यह स्थिति यही बताती है कि पुलिस साइबर ठगी की रोकथाम के लिए तत्पर नहीं। हैरानी नहीं कि इससे साइबर अपराधियों का दुस्साहस बढ़ रहा है। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि आम तौर पर हड़पी गई राशि लोगों को वापस नहीं मिल पाती, क्योंकि पुलिस की इसमें दिलचस्पी नहीं होती। निःसंदेह बेलगाम होती साइबर ठगी पर ही सुप्रीम कोर्ट सरकारों के हिस्से का काम करने के लिए सक्रिय नहीं हुआ। ऐसे न जाने कितने मामले हैं, जो सरकारों को करने चाहिए, लेकिन उनमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों को सशक्त करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि गैर-मोटर चालित वाहन और पैदल चलने वालों की गतिविधियों को नियमित किया जा सके और हादसे रोके जा सकें। उसने राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों के रखरखाव के लिए मानक निर्धारित करने का भी निर्देश दिया, ताकि सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन मिले। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने गलत लेन में गाड़ी चलाने और कारों पर अनधिकृत हूटर बजाने जैसे सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी कठोर नियम बनाने को कहा। क्या ये ऐसे काम हैं, जिनसे केंद्र अथवा राज्य सरकारें अनभिज्ञ हों? एक ऐसे समय जब भारत में मार्ग दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही हो, तब सरकारों को सड़क हादसे रोकने के लिए स्वतः सक्रिय होना चाहिए, लेकिन सच यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इतना अवश्य है कि जब कभी किसी मार्ग दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोग मरते हैं तो अफसोस जताकर और मुआवजे की घोषणा करने में देर नहीं की जाती। बहुत दिन नहीं हुए जब बिल्डरों और बैंकों की ओर से ठगे गए लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि रेरा अथवा अन्यत्र उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बैंकों और बिल्डरों ने कई शहरों में सबवेंशन स्कीम के तहत हजारों फ्लैट खरीदारों के साथ ठगी की है, तब उसने सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए। क्या यह काम सरकारों को नहीं करना चाहिए था? किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई मामला अपने हाथ में लेता है तो उसका समाधान हो जाता है। कटु सत्य यह है कि अनेक मामलों की लगातार सुनवाई करते रहने के बाद भी वह समस्या का समाधान नहीं कर पाता। इसका सबसे सटीक उदाहरण है उसकी नाक के नीचे अर्थात दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से मुक्ति न मिलना।

जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल होने पर क्या लौट पाएगा पुराना रुतबा

> इसके पूर्व पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रविवार को मुलाकात की थी। इसके बाद से चर्चा चल पड़ी थी कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन क्या फैसला लेगी, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर ऐतिहासिक कदम उठाया था।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा 2019 में खत्म कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी है, ताकि इसका पूरा राज्य का दर्जा वापस मिल सके। हालांकि, अभी तक पूरा राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इस बीच, पूरे राज्य का दर्जा मिलने की संभावना को लेकर अहम संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने दोहराया कि इस मामले पर जल्द ही फैसला आ सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब घाटी में राजनीतिक दल लंबे समय से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए मेघवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील बताया था । उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि जम्मू-कश्मीर अपने अधिकार वापस पाएगा, इसलिए ऐसा जरूर होगा। इसे एक प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इस बारे में जल्द ही फैसला सुनने को मिल सकता है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अनुसार कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क रहा है और बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, लोग संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने यह भी माना कि इस प्रोसेस में उम्मीद से ज़्यादा समय लगा है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग लंबे समय से ₹अच्छी खबर₹ का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें बहुत देर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद डेढ़ साल से बनी हुई है और सरकार को जल्द ही कोई फैसला लेना चाहिए। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ-साथ प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था। इसके बाद से लगातार जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल करने की मांग उठाई जाती रही। अब अगर छह साल बाद जम्मू-कश्मीर का पूर्ण दर्जा बहाल भी कर दिया जाता है तब भी विशेष राज्य वाला पुराना रुतबा हासिल नहीं हो सकेगा? अब छह साल के बाद क्या फिर जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है? ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को सरकार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है। दस महीने पहले ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे रखी है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को भेज रखा है, जिस पर फैसला मोदी सरकार को लेना बाकी है । बताया जाता है कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करने के लिए संसद का रास्ता अपनाना होगा। इसीलिए उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार, केंद्र से राज्य के लिए दर्जा बहाली की मांग कर रही है। मोदी सरकार ने जिस तरह से संसद के जरिए धारा 370 को समाप्त किया था और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुर्नगठित किया गया था। उसी तरह से सरकार को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। यह बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत करने होंगे। जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका अर्थ है कि इसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। जम्मू-कश्मीर की अपनी विधानसभा है, लेकिन पूर्ण राज्य की तुलना में उसे कम शक्तियां हासिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस और कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन रहती है। इसके अलावा जमीन का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास होता, जिसे उपराज्यपाल के जरिए सरकार नियंत्रित करती है। उमर अब्दुल्ला लंबे समय से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के दूसरे नेता भी लगातार यह मांग उठा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। केंद्र की मोदी सरकार भी कह चुकी है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कई मंचों से कह चुके हैं कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन यह सार्वजनिक मंच पर नहीं बताया जा सकता कि यह कब होगा। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में है, लेकिन समय-सीमा तय नहीं है। हाल ही में पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला की तारीफ करते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों को पर्यटन के जरिए जोड़ने की यह कोशिश सराहनीय है। पिछले दिनों ऑल जम्मू-कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी । इस दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दे उठाए। उन्होंने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की बात भी कही। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जम्मू-कश्मीर के राज्य बहाली मोदी सरकार करती है तो फिर कई चीजें बदल जाएंगी। जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे।सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा यानी राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे, उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं रहेगा। राज्य की बहाली से आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में राज्य की सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10 फीसदी मंत्री बनाए जा सकते हैं, राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का यह बंधन भी खत्म हो जाएगा और विधायकों की संख्या के 15 फीसदी तक विधायक मंत्री बनाए जा सकेंगे।

■ अशोक भाटिया

सरसों, चना, मसूर ...

पुनीत उपाध्याय

फरवरी की यह गर्मी नहीं आम, फूड चेन पर पड़ सकता है असर, सेहत पर भी खतरा

फरवरी को सर्दी का महीना माना जाता है लेकिन तापमान को लेकर अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलने लगा है। तपिश गर्मी का अहसास कराने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 16 फरवरी को साल का सबसे गर्म दिन रहा। सुबह की ठंड कम हो रही है और कोहरा मुश्किल से दिख रहा है। दिन का तापमान भी 30 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। ऐसी गर्मी आम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में हाल में प्रकाशित एक आलेख के अनुसार चल रहे सर्दियों के मौसम के बावजूद मुंबई में असामान्य रूप से ज़्यादा तापमान में तप रहा है पिछले हफ़्ते अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से 3.4 डिग्री ज़्यादा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में हालिया बढ़ोतरी का कारण पूर्वी हवाओं का आना या समुद्र के बजाय ज़मीन की तरफ़ से आने वाली गर्म हवाओं को बताया है। आईएमडी के वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से निचले लेवल पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं जो ज़मीन से गर्म हवाओं के आने का इशारा है। इससे पिछले हफ़्ते टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में आमतौर पर अरब सागर से आने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। ज़मीन पानी के मुकाबले तेज़ी से गर्म होती है और अंदरूनी इलाकों से आने वाली हवाएं गर्म सूखी हवा लाती हैं जिससे दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस सीज़न में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कम देखे गए हैं. ये वे वेदर सिस्टम हैं जो आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में बादल, बारिश या स्नोफॉल लाते हैं और वेस्टर्न इंडिया में टेम्परेचर कम करने में मदद करते हैं। साल 2025 की फरवरी 125 साल में सबसे गर्म महीना था। इससे पहले 2024 को 1901 के रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। एक्सपर्ट के अनुसार तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकती है। इसलिए बढ़ते तापामान के लिए बेहतर अर्बन प्लानिंग, ज़्यादा ग्रीन कवर और बेहतर वॉटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बेहतर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम भी अब जरुरी हो गया है। डाउन टू अर्थ में छपे एक अन्य आलेख के अनुसार देशभर मे 36 में से 27 शहरों में फरवरी के पहले 15 दिनों के दौरान अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान भी ऊंचा रहा। 20 राज्यों में पहले 15 दिनों में से कम से कम 10 दिनों तक रात का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। उत्तर भारत में बेमौसमी गर्मी का असर खास तौर पर अधिक स्पष्ट रहा। यहां 27 में से 15 शहरों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए। आमतौर पर कड़ाके की सर्दी के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में मौसमी पैटर्न से यह बड़ा अंतर था। नई दिल्ली, जयपुर, जम्मू, हिसार, लुधियाना, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में अधिकतम और रात का तापमान इस समय के औसत से कई डिग्री अधिक रहा और कई बार 25 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार तेज गर्मी से गेहूं की फसल समय से पहले पक सकती है। इसके उत्पादन में कमी आ सकती है। 2022 के मार्च महीने में लू के कारण गेहूं फसल पर असर पड़ा था। सरसों, चना, मसूर और मटर समय से पहले फूल दे सकती हैं जिससे फलियों का विकास कमजोर रहेगा। पैदावार घट सकती है। गर्म परिस्थितियां चेंपा और अन्य रस चूसने वाले कीटों की तेजी से वृद्धि के लिए भी अनुकूल हो सकती हैं।आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी और मटर जैसी सब्जी फसलें भी कंद बनने, गांठ विकसित होने, फूल आने और फल लगने जैसे महत्वपूर्ण चरणों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

करण वाही ...

सुभाष शिरढोनकर

दोबारा शादी का प्लान बना रही हैं जेनिफर विंगेट

खबरें आ रही हैं कि टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट जल्द ही टीवी के पॉपुलर एक्टर करण वाही के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इसके पहले जेनिफर ने साल 2012 में बिपाशा बसु के वर्तमान पति करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी लेकिन शादी के दो साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया था। इस तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं कि करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की शादी बिपाशा बसु की वजह से टूटी थी । दरअसल करण तब बिपाशा के साथ फिल्म 'अलोन' (2015) में काम कर रहे थे। उसी दौरान दोनों के बीच अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गईं। बाद में करण सिंह ग्रोवर ने जेनिफर को तलाक देकर 30 अप्रैल 2016 को बाकायदा बिपाशा बसु से शादी की । 'रीमिक्स' में रणवीर और 'दिल मिल गए' में डॉ. सिद्धांत की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों पर छा जाने वाले करण वाही अब तक 'मेरे घर आई एक नन्ही परी', 'कुछ तो लोग कहेंगे', धूप किनारे', 'कहानी हमारी...दिल दोस्ती दीवानेपन की' और 'तेरी मेरी लव स्टोरीज' जैसे कई हिट शोज में नजर आ चुके है। करण वाही एक्टर नहीं, क्रिकेटर बनना चाहते थे। अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल होकर विराट कोहली और शिखर धवन के साथ वे जमकर चौके-छक्के लगा चुके हैं। एक बार क्रिकेट खेलते वक्त उन्हें गंभीर चोट आई और बस उसके बाद पिता के कहने पर क्रिकेट छोड़कर पिता के बिजनेस में हाथ बंटाने लगे। लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग की दुनिया में खींच लाई. उन्होंने टीवी शो 'रीमिक्स' से एक्टिंग में डेब्यू किया और उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। 'खतरों के खिलाड़ी' और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शो में भी करण वाही की एपीरियंस काफी जबर्दस्त थी। 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' में करण कॉमेडी करते हुए भी नजर आए थे। इसके अलावा वे अब तक कई टीवी शोज होस्ट भी कर चुके हैं। करण वाही ने परिणीति चोपड़ा स्टारर 'दावत-ए-इश्क' (2014) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उसके बाद वे उर्वशी रौतेला स्टारर 'हेट स्टोरी 4' (2018) में राजवीर खुराना के किरदार में नजर आए थे। शादी टूटने के बाद भी जेनिफर विंगेट मजबूत रही और अपनी करियर में खूब सफलता हासिल की। 40 की हो चुकी जेनिफर विंगेट ने इस उम्र में भी अपने फिगर को एकदम परफेक्ट रखा है। जेनिफर अक्सर अपने ग्लैमरस अवतार के लिए चर्चाओं में रहती हैं। उनका काम और स्टाइलिश अंदाज हर किसी को बेहद पसंद आता है। उनके ग्लैमरस लुक और खूबसूरती पर दर्शक पूरी तरह मंत्र मुग्ध नजर आते हैं। जेनिफर ने 10 साल की उम्र में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' (1995) से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म 'राजा की आएगी बारात' (1997) में एक स्कूल जाने वाली बच्ची का खूबसूरत किरदार निभाया। फिल्म 'कुछ ना कहो' (2003) में उन्होंने ऐश्वर्या राय की बेटी पूजा के किरदार में स्क्रीन शेयर किया।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

राजेश कुमार पासी

अपनों के निशाने पर राहुल गांधी

ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे कांग्रेस के नेताओं का धैर्य जवाब दे रहा है। इसकी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेसियों को धीरे-धीरे अहसास होने लगा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। पूरा देश कांग्रेस के पतन को देख रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेता इसे देख न रहे हों। गांधी परिवार के दो बड़े वफादार नेताओं ने राहुल की कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर दिया है। मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कुछ समय पहले 'संगठन की शक्ति' के नाम पर एक बयान दिया था जिसका अप्रत्यक्ष रूप से निशाना राहुल गांधी ही थे । दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर पोस्ट करके लिखा था कि चित्र बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने लिखा था कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और और जनसंघ-बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है। इससे यह संदेश गया कि दिग्विजय सिंह भाजपा और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। जब इस बारे में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि इसका क्या मतलब है, क्या वो कांग्रेस के संगठन में सुधार चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो आरएसएस और भाजपा के घोर विरोधी हैं, उन्होंने केवल संगठन की तारीफ की है। उनसे पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस के संगठन में सुधार चाहते हैं। उनका कहना था कि इसमें सुधार की गुंजाइश है और हर संगठन में सुधार की गुंजाइश रहनी चाहिए । उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मूल रूप में एक आंदोलन की पार्टी है लेकिन अब किसी आंदोलन को वोटों में तब्दील करने में हम कमजोर पड़ जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने उनके बयान पर चुप्पी साध ली थी और कहा था कि दिग्विजय सिंह ने बैठक में संगठन में सुधार की कोई बात नहीं की है। 19 दिसम्बर को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ कांग्रेस संगठन पर भी ध्यान दें। देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने यह बता दिया था कि वो कांग्रेस के वर्तमान संगठन से खुश नहीं हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी और उनके कुछ नजदीकी नेताओं पर सीधा हमला कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने सीधा हमला नहीं किया था लेकिन मणिशंकर अय्यर ने तो नाम लेकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वो गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हैं लेकिन राहुलवादी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो भूल गए हैं कि मैं भी पार्टी में हूँ। इसके अलावा उन्होंने जयराम रमेश, शशि थरूर, पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल पर भी तंज कसा। कांग्रेस इस बार केरल में अपनी सरकार बनने की उम्मीद कर रही है लेकिन मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस केरल में नहीं जीतेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह बयान केरल में ही दिया है। उनका कहना है कि आगामी चुनाव के बाद भी विजयन मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस ने उनके बयानों से किनारा कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का अब कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, वो अपनी निजी हैसियत से बोल रहे थे। इससे चिढ़ कर अय्यर ने पवन खेड़ा को कठपुतली बता दिया। उन्होंने कहा कि खेड़ा दूसरों के इशारे पर बोलते हैं और उनके प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता पद पर ऐसी नियुक्ति पार्टी की मूर्खता को दर्शाती है. वो केवल जयराम के इशारों पर बोलते हैं। वह प्रवक्ता न होकर, तोता हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पर हमला करते हुए उन्हें गुंडा करार दिया। अय्यर ने कहा कि आप कल्पना करें कि वेणुगोपाल ने वह पद संभाल रखा है, जो कभी सरदार पटेल के पास था। शशि थरूर के बारे में कहा कि वो मोदी सरकार में विदेश मंत्री का पद लेना चाहते हैं। उन्होंने शशि थरूर को सबसे बड़ा गैरसिद्धान्तवादी करियरवादी बताया और कहा कि वो नरेंद्र मोदी की कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सबसे उपयुक्त व्यक्ति बताया । उन्होंने कहा कि स्टालिन नारेबाजी से दूर रहकर संघवाद और नीतिगत मुद्दों को उठाते हैं और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि स्टालिन 'वोट चोर, गद्दी छोड़' और 'सूट-बूट की सरकार' जैसे नारे भी नहीं देते। उन्होंने केरल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं जीतेगी क्योंकि कांग्रेस नेता कम्युनिस्टों से जितनी नफरत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा एक-दूसरे से नफरत करते हैं। दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, हालांकि वो अब पहले की तरह सक्रिय नहीं हैं। वैसे भी इस समय कांग्रेस में राहुल गांधी और उनकी जुंडली के कुछ नेता ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन पर आरोप लगाया था जिसका मतलब था कि कांग्रेस में भाजपा की तरह कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उनके द्वारा भाजपा और संघ के संगठन की तारीफ करना ही कांग्रेस के संगठन की कमी की ओर इशारा था। मणिशंकर अय्यर ने कोई इशारा नहीं किया है, सीधी बात की है। देखा जाए तो उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता मानने से मना कर दिया है। गांधी परिवार की भक्ति भी उन्होंने नहीं छोड़ी है, इसलिए कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि राहुल गांधी से निराश होकर कांग्रेस छोड़ने वालों की गिनती करना मुश्किल है। जहां कुछ नेता राहुल गांधी के रवैये से परेशान होकर कांग्रेस को अलविदा बोल चुके हैं तो कुछ नेता कांग्रेस में अंधकारमय भविष्य को देखते हुए कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। राहुल गांधी के आसपास ऐसे नेताओं का जमघट है, जिनका जनता में कोई समर्थन नहीं है। देखा जाए तो राहुल गांधी की सलाहकार मंडली में सोशल मीडिया में दिखने वाले नेताओं का दबदबा है। ये नेता मीडिया में दिखाई देते हैं लेकिन जनता में इनकी पकड़ नहीं है, इसलिए इन्हें जनता के मुद्दों की भी समझ नहीं है। अय्यर ने राहुल गांधी के नारों का मजाक बनाकर बता दिया है कि राहुल गांधी के नारे हवा-हवाई हैं जिनका जनता में कोई असर नहीं है। देखा जाए तो राहुल गांधी हवा-हवाई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार से भिड़े रहते हैं। राहुल गांधी को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है.

C M Y K

67 साल में जम्मू-कश्मीर पहली बार फाइनल में

बंगाल को 6 विकेट से हराया, आकिब नबी ने 9 विकेट लिए

नई दिल्ली, एजेंसी

67 साल के घरेलू क्रिकेट इतिहास में पहली बार जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। कल्याणी में खेले गए रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने दो बार की पूर्व चैंपियन बंगाल को 6 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। जीत के लिए मिले 126 रनों के छोटे लक्ष्य को टीम ने चौथे दिन 34.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वंशज ने 43 रन बनाए, जबकि IPL स्टार अब्दुल समद 30 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत तक पहुंचाया। इस जीत के हीरो तेज गेंदबाज आकीब नबी रहे, जिन्होंने मैच में कुल 9 विकेट लेकर बंगाल की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने पहली पारी में 42 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान भी दिया। जम्मू-कश्मीर ने पहली बार 1959-60 के सीजन में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया था। शुरुआत में इस टीम को एक कमजोर टीम माना जाता था। टीम को अपनी पहली जीत दर्ज करने में ही 44 साल लग गए थे, जब 1982-83 में उन्होंने सर्विसेज को हराया था। 2013-14 में टीम पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंची थी। इस सीजन में कोच अजय शर्मा और कप्तान पारस डोगरा के मार्गदर्शन में टीम ने मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और हैदराबाद जैसी बड़ी टीमों को हराकर अपना लोहा मनवाया। तेज गेंदबाज अकीब नबी के लिए यह सीजन किसी सपने जैसा रहा है। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ 12 विकेट लेने वाले नबी ने सेमीफाइनल में भी 9 विकेट चटकाए। इस सीजन में उनके कुल विकेटों की संख्या 55 हो गई है।

बंगाल के इंटरनेशनल स्टार्स फेल रहे

बंगाल की टीम में मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद जैसे चार इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल थे। इसके बावजूद टीम दूसरी पारी में महज 99 रनों पर सिमट गई। बंगाल ने पहली पारी में 328 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 302 रन बनाए। दूसरी पारी में अकीब नबी की घातक गेंदबाजी के सामने बंगाल का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। आकाश दीप ने दूसरी पारी में 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन वे हार नहीं टाल सके।

- 41 साल के कप्तान पारस डोगरा ने मैच के दौरान रणजी ट्रॉफी में अपने 10,000 रन पूरे किए।
- आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में 55 विकेट लिए।

समद की आक्रामक बैटिंग और वंशज का छक्का

मैच के चौथे दिन जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 83 रनों की जरूरत थी और उनके 8 विकेट सुरक्षित थे। सुबह के सत्र में शुभम पुंडीर (27) और कप्तान पारस डोगरा (9) जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया था। इसके बाद अब्दुल समद और 22 साल के युवा वंशज शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 55 रनों की अटूट साझेदारी हुई। समद ने अपनी 27 गेंदों की पारी में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर बंगाल के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया।

> "41 साल के कप्तान पारस डोगरा ने मैच के दौरान रणजी ट्रॉफी में अपने 10,000 रन पूरे किए। वे वसीम जाफर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी से होते हुए जम्मू-कश्मीर पहुंचे डोगरा ने पहली पारी में 58 रनों की जुझारू पारी खेली थी, जिसने जीत की नींव रखी।"

प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी बधाई

इस ऐतिहासिक जीत पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा,'यह खिलाड़ियों की मेहनत और कोचिंग स्टाफ के अनुशासन का नतीजा है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार किया है। मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे खिलाड़ी भारतीय टीम में भी अहम भूमिका निभाते दिखेंगे।'

फास्ट न्यूज

सीनियर एक्ट्रेस प्रवीना देशपांडे का निधन

नई दिल्ली। सीनियर एक्ट्रेस प्रवीना देशपांडे का मंगलवार को निधन हो गया। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस के परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। जिसके बाद मंगलवार दोपहर मुंबई के अंधेरी स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक्ट्रेस समय से कैंसर से जूझ रही थीं। 2019 में उन्हें मल्टीपल मायलोमा डायग्नोज हुआ था।

तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने

ढाका। बांग्लादेश में BNP अध्यक्ष तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले आज दोपहर में BNP के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वह दो महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई है। इनमें एक हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी और एक बौद्ध मंत्री दिपेन देवान चकमा भी शामिल है। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। सभी 24 राज्य मंत्री नए हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया।

शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 18 फरवरी को फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 83,400 और 25,700 पर कारोबार कर रहा है। IT, एनर्जी और रियल्टी शेयर्स में गिरावट है। इंफोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक और TCS के शेयर में करीब 2% की गिरावट है। वहीं मेटल और FMCG शेयर्स में बढ़त है। जनवरी 2026 में FIIs ने कुल 41,435 करोड़ के शेयर्स बेचे थे।

अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आए राजपाल यादव

कहा- आरोपों के खिलाफ हर जगह जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं

नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। मंगलवार को रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह जेल से बाहर आए, जिसके बाद उन्होंने उन्हें मिले लोगों के सपोर्ट का आभार जताया। बता दें कि चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। मीडिया से बातचीत में राजपाल यादव ने कानूनी सवालों पर सीधे कमेंट करने से बचते हुए कहा कि पूरी जानकारी के लिए उनके वकील उपाध्याय से पूछा जा सकता है। राजपाल यादव ने कहा कि वह पिछले 30 सालों से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्हें इंडस्ट्री और दर्शकों का भरपूर साथ और प्यार मिला, जिसकी बदौलत वह करीब 250 फिल्मों में काम कर सके। उन्होंने कहा कि बीते सालों में अदालत के आदेशों का पालन करते हुए वह नियमित रूप से पेश होते रहे हैं और भविष्य में भी जहां आदेश होगा, वहां उपस्थित रहेंगे। राजपाल ने अपने फैंस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर और उसके बाहर भी उन्हें लोगों का समर्थन मिला है। एक्टर ने कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है, तो वह 100 प्रतिशत हर जगह जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं। बातचीत के अंत में उन्होंने हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया।

इंस्टाग्राम पर पिता को याद कर एक्टर ने लिखा- पापा

सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन

मुंबई, एजेंसी

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया। इस बात की जानकारी मंगलवार शाम एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने पिता के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए श्रद्धांजलि दी और अपने पिता को याद किया। बता दें कि सिद्धार्थ के पिता सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धार्थ के पिता का शनिवार, 14 फरवरी को दिल्ली में निधन हुआ। पोस्ट के कैप्शन में सिद्धार्थ ने लिखा कि उनके पिता ऐसे इंसान थे, जो हमेशा मूल्यों पर टिके रहे। वे अनुशासित थे, लेकिन सख्त नहीं; मजबूत थे, पर अहंकारी नहीं। जीवन की कठिन परीक्षाओं के दौरान भी उन्होंने पॉजिटिव सोच बनाए रखी। उन्होंने आगे लिखा, "मर्चेंट नेवी कैप्टन के रूप में समुद्रों का नेतृत्व करने से लेकर बीमारी का साहस से सामना करने तक, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। स्ट्रोक के बाद व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उनका हौसला अडिग रहा।" उन्होंने आगे लिखा, "मर्चेंट नेवी कैप्टन के रूप में समुद्रों का नेतृत्व करने से लेकर बीमारी का साहस से सामना करने तक, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। स्ट्रोक के बाद व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उनका हौसला अडिग रहा।"

सिद्धार्थ ने पिता की कई तस्वीरें कीं शेयर कीं

सिद्धार्थ ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर पिता के साथ अपनी बचपन से लेकर हाल के समय तक की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें पिता के साथ बिताए पल दिखे।

> *"कियारा ने कहा कि वे हमेशा परिवार के साथ खड़े रहे और बिना किसी अपेक्षा के सबको प्यार देते रहे। उनकी कहानियां, हंसी, सादगी और मजबूत व्यक्तित्व हमेशा याद रहेंगे। वर्कफ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ आखिरी बार फिल्म परम सुंदरी में नजर आए थे। पर्सनल लाइफ की बात करें, सिद्धार्थ और कियारा की पहली संतान, बेटी सरायाह मल्होत्रा का जन्म 15 जुलाई 2025 को मुंबई के रिलायंस अस्पताल में हुआ था।"*

कियारा ने भी इमोशनल पोस्ट शेयर की

सिद्धार्थ के पिता के निधन पर कियारा ने भी इमोशनल पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से ही पापा ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। उनका प्यार, समझदारी और स्नेह पूरे परिवार को संभाल कर रखने वाला था। सिद्धार्थ ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा, "पापा, आपकी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी विरासत है।

अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना

अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले- ईरान हमारी शर्तें मानने को तैयार नहीं, ट्रम्प के पास दूसरे रास्ते भी मौजूद

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे हैं। इंडिपेंडेंट फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया है। यह जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में हुई दूसरी दौर की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। इन बयानों से साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अभी भी नाजुक दौर में है। ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान अमेरिकी मांगें नहीं मानता, तो अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करेगा। एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मुताबिक, इसका मकसद खुफिया और ऑपरेशनल क्षमताओं की जांच करना है। समुद्री सुरक्षा कंपनी ईओएस रिस्क ग्रुप ने कहा कि इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों को पहले ही रेडियो पर चेतावनी दी गई थी। जनवरी के अंत में हुए इसी तरह के अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कड़ा बयान जारी किया था। उसने कहा था कि ईरान को अंतरराष्ट्रीय हवाई और समुद्री क्षेत्र में पेशेवर तरीके से काम करने का अधिकार है, लेकिन वह अमेरिकी वॉरशिप या ट्रेड जहाजों को परेशान न करें। हॉर्मुज जलडमरूमध्य अपनी सबसे संकरी जगह पर करीब 33 किलोमीटर (21 मील) चौड़ा है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और ईरान का तेल और गैस यहीं से बाहर जाता है। ज्यादातर खेप एशिया के लिए होती है।

अमेरिका ने रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट भेजे

अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट की ओर जाते देखे गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि विमान लंबे समय तक ऑपरेशन की तैयारी में हैं। इस बीच, अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि USS जेराल्ड आर. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से रवाना होकर मिड-अटलांटिक में पहुंच चुका है और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अगले चार-पांच दिन में उसके पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि फोर्ड के साथ तीन गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर, USS माहान, USS बैनब्रिज और USS विन्सटन चर्चिल भी हैं। इससे पहले USS अब्राहम लिंकन और अन्य महत्वपूर्ण अमेरिकी एयर और नेवल एसेट्स भी इस साल की शुरुआत में क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं। इससे अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी और मजबूत हुई है।

ईरान ने ऑपरेशनल क्षमताओं की जांच के लिए नौसैनिक अभ्यास शुरू किया

ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यह कदम लाइव-फायर सैन्य अभ्यास के दौरान उठाया गया। ईरान ने सोमवार को इस नए अभ्यास की घोषणा की थी। इसे 'स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' नाम दिया गया। फारस की खाड़ी के संकरे हिस्से में मिसाइल परीक्षण किए गए। ईरानी मीडिया ने सुरक्षा और समुद्री कारणों का हवाला देते हुए कहा कि यह बंदी कुछ घंटों के लिए रहेगी।

कुत्तों-मुसलमानों में से एक को चुनना आसान : रैंडी फाइन

फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट ने लिखा था- न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन के एक सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने X पर लिखा कि अगर कुत्तों और मुसलमानों में से एक को चुनना पड़े तो यह मुश्किल फैसला नहीं है। दरअसल, रैंडी फाइन ने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क में एक फिलिस्तीनी-अमेरिकी एक्टिविस्ट नरदीन किसवानी की पोस्ट के जवाब में की थी। किसवानी ने लिखा था कि कुत्ते अपवित्र हैं। ऐसे समय में जब न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, कुत्तों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इन्हें बैन करना चाहिए। इस पर फाइन ने कहा कि दुनिया में 57 ऐसे देश हैं, जहां शरिया कानून लागू है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वहीं चले जाइए। अमेरिका 58वां मुस्लिम देश नहीं बनेगा। बाद में किसवानी ने कहा कि वह बस मजाक कर रही थीं। यह न्यूयॉर्क में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की गंदगी को लेकर चल रही बहस से जुड़ा था।

फाइन पर मुसलमानों को अमानवीय दिखाने का आरोप

किसवानी ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने फार्म पर एक कुत्ते को गोली मारने की बात कही थी। किसवानी ने लिखा, 'क्रिस्टी नोएम ने अपने ही कुत्ते को गोली मारने की बात कही और ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम कह दे कि शहर पालतू जानवरों के लिए सही जगह नहीं है तो उसे मौत की धमकियां मिलने लगती हैं।'

कार्यक्रम : बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स भी किया, एक्सपर्ट्स बोले-चीन ने रोबोटिक्स में अमेरिका को पछाड़ा

चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस वायरल

वॉशिंगटन, एजेंसी

चीन ने सोमवार को दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखाई। एक कार्यक्रम में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मार्शल आर्ट्स और डांस किया। करीब 25 रोबोट्स बच्चों के साथ तलवार भांजते, बैकलिफ्ट करते और डंडे घुमाते हुए डांस करते दिखाई दिए। खास बात यह रही कि एक भी रोबोट गिरा नहीं। यह प्रदर्शन देख दुनिया हैरान रह गई। कई लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर रोबोट अब नाच सकते हैं और कुंग फू कर सकते हैं, तो वे और क्या कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल अलग था। पिछले साल रोबोट्स सिर्फ रुमाल घुमाते और साधारण हरकतें करते नजर आए थे। लेकिन एक साल में सबकुछ बदल चुका है। चीन दुनिया को खासकर अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वह तकनीक में बहुत आगे निकल चुका है। स्टीलर के मुताबिक सिर्फ एक साल में रोबोट्स की क्षमता में बड़ा बदलाव आया है। अब उनकी चाल-ढाल और मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। इससे साफ है कि यूनिट्री जैसी कंपनियां रोबोट के 'दिमाग' यानी एआई सॉफ्टवेयर को मजबूत बनाने पर काम कर रही हैं, ताकि ये रोबोट भविष्य में फैक्ट्रियों में बारीक और असली काम भी कर सकें। रिसर्च फर्म ओम्डिया के अनुसार, पिछले साल दुनियाभर में भेजे गए लगभग 13 हजार ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से 90 प्रतिशत चीन से थे। यह अमेरिकी कंपनियों से काफी आगे है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि इस साल चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट की बिक्री दोगुने से ज्यादा बढ़कर 28 हजार यूनिट तक पहुंच सकती है। दुनिया के सबसे रईस शख्स इलॉन मस्क का कहना है।

टेक्नोलॉजी का शोकेस है गाला, रोबोट कंपनियों को फायदा

एशिया में टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी के प्रमुख जॉर्ज स्टीलर ने कहा कि जिस गाला में इन रोबोट्स ने प्रदर्शन किया, वह कई सालों से चीन की तकनीकी ताकत दिखाने का बड़ा मंच रहा है। इसी मंच पर चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम, ड्रोन और रोबोट जैसी नई तकनीकों को दुनिया के सामने पेश करता रहा है। उन्होंने कहा कि इस गाला की सबसे खास बात यह है कि यहां सरकार की औद्योगिक नीति और टीवी के बड़े शो के बीच सीधा संबंध दिखाई देता है। यानी जिन कंपनियों को इस मंच पर अपने प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिलता है, उन्हें बाद में सरकारी ऑर्डर, निवेशकों की दिलचस्पी और बाजार में आसानी से एंट्री जैसे फायदे मिलते हैं।

चांदी ₹4 हजार बढ़कर ₹2.37 लाख पर पहुंची

नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमत में आज यानी 18 फरवरी को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, एक किलो चांदी 4 हजार रुपए बढ़कर 2.37 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले कल ये 2.33 लाख रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 98 रुपए महंगा होकर 1.52 लाख रुपए पर पहुंच गया है। सर्राफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। 2025 में सोना 57 हजार (75%) बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76 हजार का था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1.33 लाख रुपए हो गया। चांदी इस दौरान 1.44 लाख (167%) बढ़ी। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी 86 हजार की थी, जो साल के आखिरी दिन 2.30 लाख प्रति किलो हो गई। इक्विनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर और एमडी जी. चोक्कालिंगम ने कहा कि सोने-चांदी के साथ ही कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स अत्यधिक अस्थिर रहेंगे। अगले 6 महीनों में इनके दाम कम से कम 10% और घट सकते हैं।

दुनियाभर में यूट्यूब की सर्विस डेढ़ घंटे तक ठप, लाखों यूजर्स को हुई परेशानी

एप खोलने पर 'समथिंग वेंट रॉन्ग' का मैसेज दिखा, रिकमेंडेशन सिस्टम में खराबी आई

नई दिल्ली, एजेंसी

दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब की सर्विस अचानक ठप हो गई। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, दुनियाभर में सुबह करीब 6 बजकर 20 मिनट से लगभग 8 बजे तक लाखों यूजर्स को इसे एक्सेस करने में परेशानी हो रही थी। सबसे ज्यादा दिक्कत इसके मोबाइल एप में आई जहां यूजर्स को समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज दिख रहा था। हालांकि जब इसे दो-तीन बार रिफ्रेश किया तो वीडियोज दिखने लगे थे। लेकिन पूरी तरह से ये काम नहीं कर रहा था। वहीं इसकी वेबसाइट एक्सेस हो रही थी। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक अमेरिका में करीब 2.83 लाख लोगों ने यूट्यूब न चलने की शिकायत की। भारत में आज सुबह 7 बजे के करीब डाउनडिटेक्टर पर शिकायतों का आंकड़ा 18 हजार को पार कर गया। यहां 71% यूजर्स एप इस्तेमाल में दिक्कत हुई। यूट्यूब की टीम ने इस आउटेज को लेकर आज सुबह 07:26 मिनट पर एक X पोस्ट में कहा- अगर आपको अभी यूट्यूब चलाने में दिक्कत आ रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं और जो भी अपडेट होगा, हम यहां जानकारी देंगे। इसके बाद एक और अपडेट में यूट्यूब ने कहा कि हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम में एक खराबी की वजह से यूट्यूब के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे होमपेज, यूट्यूब एप, यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब किड्स पर वीडियो नहीं दिख रहे थे। होमपेज अब ठीक हो गया है, लेकिन हम अभी भी इसे पूरी तरह ठीक करने पर काम कर रहे हैं। जल्द ही और जानकारी दी जाएगी! आउटेज एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई सर्विस जैसे इंटरनेट, एप, वेबसाइट अचानक काम करना बंद कर देती है या उपलब्ध नहीं रहती। यह कुछ समय के लिए हो सकता है। जैसे कुछ मिनट से लेकर घंटों तक। इसका कारण सर्वर फेल होना, नेटवर्क समस्या, रखरखाव, मौसम की मार, हार्डवेयर खराबी या ज्यादा लोड पड़ना हो सकता हैं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगे 'भागवत गो बैक' के नारे

स्टूडेंट्स को पुलिस टांगकर ले गई, संघ प्रमुख का कार्यक्रम शुरू

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार सुबह RSS प्रमुख मोहन भागवत के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। NSUI, समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्र 'गो बैक मोहन भागवत' के नारे लगाने लगे। पुलिस ने जब छात्रों को रोकने की कोशिश की, तो नोकझोंक और खींचतान शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को ठूंस-ठूंसकर जीप और बसों में भरा। कई छात्र लेट गए, तो उन्हें टांगकर ले जाया गया। सभी छात्रों को इको गार्डन भेजा गया। इसके बाद मोहन भागवत का कार्यक्रम शुरू हुआ। भागवत दो दिवसीय लखनऊ प्रवास पर हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में संगोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में भाग लेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय में मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करने वाले छात्रों को पुलिस टांगकर ले गई।

मंगलवार को निराला नगर में भागवत सरस्वती शिशु मंदिर आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल हुए। उन्होंने सामाजिक सद्भाव से जुड़े विषयों पर विभिन्न वर्गों के लोगों के सवालों के जवाब दिए। UGC गाइडलाइंस पर भागवत ने कहा- कानून सभी को मानना चाहिए। अगर कानून गलत है, तो उसे बदलने का उपाय भी है। कानून को जातियों के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए।

> एनएसयूआई कार्यकर्ता शुभम यादव ने कहा- संघ से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि विपक्षी छात्र संगठनों को हॉल तक नहीं मिलते। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। इसके बावजूद आरआरएस प्रमुख की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

प्रदर्शन से पहले ही अलर्ट मोड़ में आई पुलिस

छात्रों के प्रदर्शन से पहले ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी। प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका पर पुलिस सुबह 5 बजे ही समाजवादी छात्र सभा के सदस्य तौकील गाजी के हॉस्टल के रूम पर पहुंच गई। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। समाजवादी छात्र सभा के कई अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया। उन्हें हसनगंज थाना ले गई।

मुगल और अंग्रेज हिंदू धर्म संस्कृति को मिटा नहीं सके

संघ प्रमुख ने कहा, अमेरिका और चीन जैसे देशों में बैठे कुछ लोग हमारी सद्भावना के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। इससे हमें सावधान रहना होगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास समाप्त करना होगा। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना होगा। जातिवाद पर मोहन भागवत ने कहा, 500 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज शासन कर चले गए।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या कहा...

- **छात्र अहमद ने कहा-** मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को देशभर के विश्वविद्यालयों में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, लेकिन यहां उन्हें सम्मान दिया जा रहा है।
- **गौरी जायसवाल ने कहा-** हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस छात्रों को रोककर रखे हुए है। हम चाहते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए। हमसे कहा जा रहा है कि बाद में आइएगा।
- पुलिस ने सुबह 5 बजे से ही छात्र सभा के छात्रों को पकड़ना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हाउस अरेस्ट कर लिया।
- पुलिस ने सुबह 5 बजे से ही छात्र सभा के छात्रों को पकड़ना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हाउस अरेस्ट कर लिया।

NSUI कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। जमकर खींचतान भी हुई।।

मुस्लिम भी संघ से जुड़ना चाहते

बैठक में पूछा गया सवाल RSS ने मुस्लिम मंच क्यों बनाया? मोहन भागवत ने कहा, मुस्लिम भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ना चाहते हैं। उनके लोगों ने मंच बनाया है। भारत निकट भविष्य में विश्व को मार्गदर्शन देगा। विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान भारत के पास ही है। उन्हें रोजगार नहीं देना है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर कहा, हिंदुओं के कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है। यह कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, वह समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं।

राहुल पर एफआईआर को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई

लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 19 फरवरी 2026 को सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। यह मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर आवेदन से संबंधित है। लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर आवेदन में लखनऊ मजिस्ट्रेट अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी गई है। यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत प्रस्तुत किया गया है। मामले की सुनवाई एकल पीठ के रूप में न्यायमूर्ति राजीव सिंह द्वारा की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया है कि संबंधित प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज

कराने का निर्देश दिया जाए। याचिका में राहुल गांधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं 318, 335, 340, 236, 237, 61, 148, 147, 152, 238, 336(3), 351 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 5 एवं 6, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 व 13 तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(बी) और 14(सी) के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने रायबरेली जिले के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने की अपील की है।

फास्ट न्यूज

टीचरों ने बच्चों पर फूल बरसाए

लखनऊ। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गईं। पहले दिन दोनों कक्षाओं की हिंदी विषय की परीक्षा है। सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक हाईस्कूल का पेपर हुआ। दोपहर 2 बजे से इंटर-मीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। यह परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर बच्चों पर फूल बरसाए गए।

अग्निवीर भर्ती में दौड़ते-दौड़ते 3 लड़कियां बेहोश

लखनऊ। महिला अग्निवीर भर्ती रैली में दौड़ते-दौड़ते 3 अभ्यर्थी गिरकर बेहोश हो गईं। लॉन्ग जंप के दौरान एक अन्य अभ्यर्थी के पैर में मोच आ गई। सभी को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। अभ्यर्थियों को 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी थी। 8 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने पर ग्रेड-वन और 8 मिनट में पूरी करने पर ग्रेड-टू दिया गया। दौड़ में सफल अभ्यर्थी 3 फीट हाई जंप और 10 फीट लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाई किया। हाई जंप और लॉन्ग जंप में अभ्यर्थियों को 3-3 चांस दिए गए। भर्ती रैली लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर एंड कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में हुई। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करीब 1000 अभ्यर्थी हिस्सा लिया। इस रैली में वही अभ्यर्थी शामिल हुईं, जिन्होंने जुलाई 2025 में ऑनलाइन सीईई परीक्षा पास की थी।

17 दिन बाद मिला लापता युवक का शव

लखनऊ। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में मंगलवार शाम इंदिरा नहर में एक युवक का शव उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान प्रियांशु (21) निवासी ग्राम कबीरपुर थाना गोसाईगंज के रूप में हुई है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए एक युवती और उसके प्रेमी पर आरोप लगाए हैं।

आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर मंत्री आवास घेरा

लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, साल 2024 से 51 तारीखों के बाद भी नहीं निकला समाधान

- बैनर-पोस्टर लेकर अभ्यर्थी मंत्री के आवास के बाहर बैठ गए।
- अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ। वर्ष 2024 की आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती में लगातार हो रही देरी को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में मंत्री डॉ. दया शंकर मिश्र 'दयालु' के आवास का घेराव किया। नाराज अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और कोर्ट में लंबित मामले के शीघ्र निस्तारण की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकारी पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है, जिसके कारण मामला लंबित बना हुआ है और नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनका कहना है कि अगर समय रहते मजबूत पैरवी की जाती तो अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने बताया कि वे लंबे समय से इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कई

प्रदेश में 60 प्रतिशत पद रिक्त

अभ्यर्थियों के मुताबिक, प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लगभग 60 प्रतिशत पद खाली हैं। सरकार की ओर से 1002 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जबकि कुल स्वीकृत पद करीब 2100 हैं। इनमें से लगभग 1200 पद अब भी रिक्त पड़े हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर पद खाली होने से आयुष और स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दवाओं के वितरण और फार्मेसी संचालन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी पार होने की कगार पर है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत और तैयारी के बावजूद नियुक्ति न होने से मानसिक और आर्थिक दोनों तरह का दबाव बढ़ रहा है।

> प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस के चलते लंबे समय से अटकी हुई है। उनके अनुसार अब तक 51 तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। लगातार मिल रही नई-नई तारीखों से अभ्यर्थियों में भारी निराशा और आक्रोश है।

बेंच-वाइज फैसला या लिखित परीक्षा कराने की मांग

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की कि कोर्ट में बेंच-वाइज निर्णय कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में प्राथमिकता से हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लंबित भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिल सके।

अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ को सौंपा ज्ञापन

तमसा संकेत, संवाददाता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने Chief Electoral Officer Uttar Pradesh को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में फार्म-7 के जरिए पी.डी.ए. और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से काटने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में सुल्तानपुर सदर, सिकंदरपुर, सरोजनी नगर, जसवंतनगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, शामली, कुंदरकी समेत कई विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए बड़े पैमाने पर फार्म-7 जमा किए जाने का आरोप लगाया गया। मुस्लिम और पी.डी.ए. मतदाताओं के नाम व ईपिक नंबर प्रिंट कर आवेदन जमा करने की शिकायत कुछ स्थानों पर बीएलओ पर दबाव बनाने और अभद्र व्यवहार के आरोप सपा ने मांग की है कि फार्म-7 से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी बीएलओ द्वारा सत्यापन के बाद ही की जाए तथा किस बूथ पर कितने फार्म जमा हुए, इसकी जानकारी प्रतिदिन

सार्वजनिक की जाए। ज्ञापन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 और 32 के तहत फर्जी आवेदन देने वालों और दोषी अधिकारियों पर एफआ-ईआर दर्ज करने की मांग की गई। सपा का आरोप है कि लॉजिकल एरर के नाम पर मतदाताओं को नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर सत्यापन करेंगे, नोटिस की विधिवत रिसीविंग कराई जाएगी और जांच के बाद ही निर्णय होगा। उन्होंने फार्म-7 थोक में जमा होने के आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। इस दौरान कमाल अख्तर, प्रभुनारायण सिंह यादव, डॉ. आर.के. वर्मा, मनोज पारस, शहजिल इस्लाम, महेंद्र नाथ यादव, डॉ. संग्राम सिंह यादव, मोहम्मद फहीम इरफान, रविदास मेहरोत्रा, सचिन यादव, पंकज मलिक, नवाब जान और राम अधार राजभर सहित कई विधायक मौजूद रहे।

नकली दरोगा पकड़ा गया

लाइटर वाली पिस्टल, नकली बुलेट मिली, कार पर लखनऊ कमिश्नर की गाड़ी का नंबर

- कानपुर पुलिस ने नकली दरोगा को गिरफ्तार किया।
- नकली दरोगा के पास से नकली लाइटर जलाने वाली पिस्टल और प्लास्टिक के कारतूस भी बरामद हुए हैं।

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। वह लाइटर जैसी दिखने वाली पिस्टल से लोगों को डराकर पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करता था। लोगों को शक न हो, इसलिए उसने कार के असली नंबर की जगह सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी। उसके पास से पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सीबीआई के कई फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं फर्जी दरोगा की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। वह उन्नाव जिले का रहने वाला है। पुलिस हिरासत में उसने बताया कि वर्दी समेत अन्य सामान दुर्गेश का है, जो खुद को

केशव प्रसाद मौर्य का पीएसओ बताता है। उसी ने सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट भी दी थी। DCP सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया- आरोपी युवक संजय कुमार को गिरफ्तार किया है, ये फर्जी दरोगा बनकर के लोगों को ठगता था। लोगों को नौकरी लगवाने के साथ-साथ ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर भी ठगी करता था। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है, इसके साथी दुर्गेश और विजय का नाम पूछताछ में सामने आया है। संजय कुमार के पास से पुलिस ने एक गाड़ी आई-20 गाड़ी बरामद की है। कार पर सरकारी वाहनों को आवंटित होने वाला फर्जी नंबर प्लेट (UP32EG2250) लगी था। गाड़ी, लखनऊ के इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। जबकि, उसका असली रजिस्ट्रेशन नंबर UP35BK8203 है। DCP सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया- मंगलवार को अनवरगंज पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में घूम रहा है जो कि फर्जी है। सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। उसने यूपी पुलिस के दरोगा की वर्दी पहन रखी थी। पूछताछ की गई तो वह फर्जी निकला। उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो फर्जी पिस्टल, आई कार्ड बरामद हुआ। ये लोगों को नौकरी और ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर ठगी करता था। कार के नंबर प्लेट के सवाल पर संजय ने बताया- गाड़ी की किस्त टूटी थी तो दुर्गेश ने कहा- ये नंबर प्लेट लगा लो। असली नंबर प्लेट तो मेरे पास रखी गई है। पुलिस के मुताबिक, दुर्गेश अभी फरार है। बताया जा रहा है, वह इस समय नौकरी से टर्मिनेट चल रहा है।

ऐलान : गठबंधन की अफवाहें, विरोधियों की घिनौनी साजिश, दिल्ली के बड़े बंगले पर भी सफाई दी

अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे : मायावती

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें फर्जी हैं। यह हमारे खिलाफ साजिश है। दरअसल, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के गठबंधन की खबरें सामने आ रही थीं। इसके अलावा तीन दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इशारों में गठबंधन का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था- बसपा से पुराने रिश्ते हैं। कई बार गठबंधन बनते और टूटते हैं। हमें उम्मीद है कि उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मायावती ने दिल्ली में हाल ही में अलॉट हुए टाइप-8 बंगले को लेकर उठ रही अफवाहों पर सफाई दी। कहा-

भाजपा सरकार ने कई बंगले अलॉट किए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से नहीं लिए गए या छोड़ दिए गए। अब मुझे टाइप-8 का सही बंगला अलॉट किया गया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। बसपा प्रमुख ने 2 जून, 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। कहा- उस घटना के बाद से ही मुझे विशेष उच्च सुरक्षा मिली हुई है, जो अब और बढ़ गई है। कांग्रेस सरकार के समय से ही मुझे टाइप-8 बंगला मिलता रहा है। इस पर घिनौनी राजनीति करना ठीक नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, 'आजकल लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय एआई जैसी चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसी बीच, कुछ स्वार्थी नेता और मीडिया जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव किसी गठबंधन में लड़ेगी। यह पूरी तरह झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक खबर है, जिसका मकसद लोगों को गुमराह करना है।' मायावती ने कहा, 'नेताओं और मीडिया को इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भरकर अपना मजाक खुद उड़ाने से बचना चाहिए। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पहले ही कई बार सार्वजनिक किया जा चुका है। खासकर 9 अक्टूबर, 2025 को

दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर मायावती को यह बंगला नंबर-34 अलॉट किया गया है।

कांशीरामजी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुई महारैली में यह साफ तौर पर घोषित किया गया था। इसके बाद किसी तरह की चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं बचती।' पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा- इन पार्टियों की सोच संकीर्ण और बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर विरोधी है। इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ है।

पृष्ठ 01 का शेष...

गलगोटिया...

इसमें 4D LiDAR तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से यह सीढ़ियां चढ़ने, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानता है। लगभग 2 से 3 लाख रुपए की कीमत वाला यह रोबोट वॉयस कमांड पर भी काम करता है और मुख्य रूप से तकनीकी रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है।

राज्यसभा की 37...

16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए तय मानक का वॉयलेट रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल होगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। आयोग के मुताबिक 5 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 1.20 लाख से ज्यादा लोगों ने डेमो कैंप में हिस्सा लिया। 1.16 लाख से ज्यादा लोगों ने मॉक वोट डाले। 10 फरवरी तक 29 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन मोबाइल डेमो वैन से कवर किए जा चुके हैं। यह अभियान EVM डेमो सेंटर और मोबाइल वैन के जरिए चलाया जा रहा है। राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनावों से काफी अलग है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं यानी जनता नहीं बल्कि विधायक इन्हें चुनते हैं। चुनाव हर दो साल में होते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 हैं। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से ही तय होता है। वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर होता है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है। राज्यसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित संख्या में मतों की आवश्यकता होती है, जिसे जीतने का कोटा (Quota) कहा जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं। खाली हो रही सीटें 7 हैं। चूंकि एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 होती है। इसलिए महाराष्ट्र में अभी एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए कम से कम 36 विधायकों की जरूरत होगी।

ईडी केंद्र का...

वहीं केंद्रीय एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी के हथियार नहीं हैं। बंगाल में ममता सरकार ने हमें धमकाया। दोनों पक्षों के बीच बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, यह हम तय करेंगे। ED ने I-PAC रेड मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ED का आरोप है कि 8 जनवरी को I-PAC के ऑफिसों पर रेड के दौरान CM ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई में रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवारई 18 मार्च तक टाल दी है। इससे पहले 3 फरवरी को सुनवाई टाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ED की जांच में बाधा डालना बहुत गंभीर मुद्दा है। I-PAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। यह राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। CBI ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की थी। पूरा मामला 2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

सुंदर पिचाई ने...

यहां उन्होंने कहा कि जल्द ही आप अपने फोन के कैमरे और आवाज का इस्तेमाल करके रियल-टाइम में किसी भी चीज को अपनी भाषा में सर्च कर पाएंगे। PM मोदी ने 16 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने इवेंट में शामिल हुए स्टार्टअप्स के पवेलियंस में जाकर उनके इनोवेशंस की जानकारी ली थी। ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ-साथ 'इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026' का भी आयोजन किया गया है। यहां दुनियाभर की कंपनियां अपने लेटेस्ट AI सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश किया है। यहां आम लोग देख सकते हैं कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में AI से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है।

मैं गांधियन...

जब उनके कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने रविवार को तिरुवनंतपुरम में भरोसा जताया कि पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वे अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में बोल रहे थे जिसके आयोजक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। अय्यर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिनके बारे में उन्हें भरोसा है कि वे अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे- वे अपनी अपील दोहरा रहे हैं कि केरल को देश का सबसे बेहतरीन पंचायती राज राज्य बनाया जाए।

अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, संविधान और लोकतंत्र बचाने का आह्वान

तमसा संकेत, संवाददाता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को कमजोर करना चाहती है और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद से उसे चिढ़ है। Samajwadi Party के राज्य मुख्यालय Lucknow में विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा की रणनीतियों से सावधान रहना होगा और नकारात्मक राजनीति से दूर रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी Ram Manohar Lohia और B. R. Ambedkar के सिद्धांतों पर अडिग है। उन्होंने कहा कि पीडीए का रास्ता ही विकल्प है और कार्यकर्ताओं को एकजुटता व आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने प्रदेश में सपा सरकार बनने का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, जबकि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति में विश्वास रखती है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने कार्यों के बजाय सपा सरकार के समय हुए विकास कार्यों को अपना बताती है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676